

सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ दायर ईडी की चार्जशीट का धार में विरोध कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, मामले को बताया राजनीतिक द्वेषता

धार। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर चार्जशीट का विरोध कर कलेक्ट्रेट में राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में कांग्रेस पदाधिकारियों ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर वर्षों पुराने नेशनल हेराल्ड मामले में राजनीतिक द्वेषता के चलते एवं केंद्र सरकार के खिलाफ बुलंद हो रही आवाज को दबाने के लिए ईडी ने चार्ज शीट दायर की है। इसका विरोध अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आन्ध्र प्रदेश प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कांग्रेसीजनों ने राष्ट्रपति के



नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलकिशोर पाटीदार,

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह नीमखेड़ा, अल्पसंख्यक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मुजीब

कुरैशी, सरदापुर विधायक प्रताप ग्रेवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष धीरज दीक्षित, एन एम शर्मा,

प्रदेश सचिव हरदेव सिंह जाट, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज सिंह गौतम शहर अध्यक्ष जसबीर सिंह टोनी छाबड़ा, जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष रोहित कामदार, प्रदेश सचिव सोहेल निसार, आशीष भाकर, राधेश्याम मुवेल्, लियाकत पटेल, जगदीश सेन, राजेश पटेल, बंटी डोड, सुनील चौहान, मोहन डामोर, अजय ठाकुर, अभिजीत तिवारी, मुकेश मालवीय, सुरेश परमार, संजय मालवीय, गोलू देवड़ा, जीतू बाबा, मुफु सैफी, मोहम्मद अली, मनीष भार्गव, शंकर चौहान, अजीत पाल सिंह, मनोहर चावड़ा, रवि योगी, वाहिद कुरैशी सहित अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित थे ज्ञापन का वाचन सरदापुर विधायक प्रताप ग्रेवाल ने किया। उक्त जानकारी मनोज चौहान द्वारा दी गई।

धार मेडिकल कॉलेज को लेकर सियासत गर्माई

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ट्वीट कर सीएम मोहन यादव पर साधा निशाना कहा- पहले से घोषित मेडिकल कॉलेज की पुरानी घोषणा को ही सीएम ने फिर दोहराया, ग्रीन बेल्ट की जमीन होने से अटका है मेडिकल कॉलेज प्रोजेक्ट

धार। मेडिकल कॉलेज को लेकर एक बार फिर राजनीति गरमा गई है। गंधवानी से विधायक और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्होंने धार में पहले से घोषित मेडिकल कॉलेज की पुरानी घोषणा को ही दोहराया है। सिंघार ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को उनके अफसर सही जानकारी नहीं दे रहे, इसलिए वे पुरानी घोषणाओं को ही फिर से मंच से दौहरा रहे हैं।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को रतलाम में आयोजित वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में धार में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही। इस पर उमंग सिंघार ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा ट्वीट किया है कि यह मेडिकल कॉलेज की कोई नई घोषणा नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कॉलेज की घोषणा पहले ही कर चुके हैं और यहां तक कि भवन का वर्चुअल भूमिपूजन भी विधानसभा चुनाव से पहले हो चुका है जिस जमीन पर मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन किया गया था, वह ग्रीन बेल्ट में आती है, जिससे मामला अटक गया। अब मुख्यमंत्री उसी घोषणा को नए अंदाज में



दोहरा रहे हैं।

ग्रीन बेल्टों की जमीन होने से अटका प्रोजेक्ट- गौरतलब है कि धार में बनने वाले मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित भूमि ग्रीन बेल्ट की है, उसके मांडिफिकेशन की प्रक्रिया अभी जारी है, हालांकि इससे पहले ही लोक स्वास्थ्यों व चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इसके निर्माण के लिए 260 करोड़ की राशि के टेंडर निकाल दिए थे। इससे पहले भी लैड यूज को नजर अंदाज करते हुए 2 करोड़ 95 लाख की

लागत से बाउंड्रीवाल बनाई गई थी। बाउंड्रीवाल निर्माण के बावजूद भी बारिश का पानी वहां घुस रहा था।

निजी हाथों में होगा संचालन- पीपीपी यानि पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के तहत निजी कंपनी द्वारा उक्त मेडिकल कॉलेज का निर्माण और संचालन किया जाएगा, लेकिन शासन भी इस में भागीदार रहेगा। इसमें हर वर्ग को इलाज के लिए न्यूनतम शुल्क निर्धारित किया जाएगा।

राष्ट्रीय मिन्य कम मेरिट छात्रवृत्ति में चयन



बाकानेर। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मींस कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना 2024-25 के परीक्षा परिणाम घोषित हुए, जिसमें

उमरवन विकासखंड के 16 बच्चों का चयन हुआ जिसमें से पांच बच्चे संकुल केंद्र कन्या उमावि बाकानेर की विद्यालयों के हैं। चयनित बच्चे कन्या उमावि बाकानेर, कु जानवी जायसवाल, मा वि धनखेड़ी, से कु निशा बेनल रुखडिया वास्केल, मा वि भुवादा से वीर बर्मन, मा वि बजटटाखुर्द से कु दीपिका का चयन हुआ है, राष्ट्रीय मींस कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना में

चयनित बच्चों को कक्षा 9 से 12वीं तक अध्ययन के लिए शासन के द्वारा 712000 की छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष प्रदाय की जाती है, यह परीक्षा कठिन होती है इसमें चयन होना बहुत बड़ी बात होती है। बच्चों की इस उपलब्धि पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी सत्यनारायण सूर्यवंशी विकासखंड स्त्रोत समन्वयक राजेश रावल, विकासखंड अकादमिक समन्वयक देवेन्द्र सोलंकी, अजय खोड़े श्याम सेन, राकेश कल्ल संकुल प्राचार्य श्रीमती किरण संजय वास्केल, संकुल के समस्त शिक्षकों ने बच्चों एवं चयनित विद्यालयों के शिक्षकों के लिए शुभकामनाएं, बधाई दिल्ली मुबारक बाद, प्रेषित की जानकारी जनशिक्षक तेजलाल पंवार द्वारा दी गई।



वर्ष 2005 में नगर निगम जबलपुर ने शहर में सीवर लाइन व नाला निर्माण वाटर ड्रेनेज योजना के नाम पर एशियन डेवलपमेंट बैंक से 196 करोड़ का कर्ज लिया था। तो सीवर लाइन का काम ही अभी तक पूरा हो पाया है और न ही नाला निर्माण ही पूर्ण हो पाया है। सीवर लाइन निर्माण में करीब एक हजार करोड़ रुपए लग चुका है और अभी कम से कम 200 करोड़ और लगना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया गया कर्ज के बदले नगर निगम जबलपुर 18 करोड़ रुपए सालाना ब्याज दे रहा है और यह सिलसिला अगले 15 साल और चलना है। इसी तरह नगर निगम जबलपुर ने 2017 में हुडको बैंक से 96 करोड़ रुपए का ऋण आवास योजना को पूर्ण करने के लिए लिया था। मगर अभी तक एक भी मकान बेच नहीं पाया है। इस 96 करोड़ रुपए कर्ज के बदले हर तिमाही 1.5 करोड़ रुपए ब्याज देना होता है। सरकार का कहना है कि राज्य के पास इतना पैसा नहीं है कि विकास कार्य का संचालन कर सके। वित्तीय घाटे के नाम पर एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक व अन्य

अधोसंरचना विकास के नाम पर कर्ज का हश्र

अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लिए जा रहे हैं और कर्ज के साथ तमाम शर्तें लादी जा रही है। मध्यप्रदेश और एडीवी की पार्टनरशिप 1999 में शुरू हुई थी। आज ऊर्जा, परिवहन, शहरी विकास, कृषि, आजीविका निर्माण, जल प्रबंधन और सिंचाई प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में एडीवी की 6 बिलियन यूएस डॉलर की मदद है। सड़क निर्माण एवं सुधार में 3 बिलियन यूएस डॉलर से 23 हजार किमी सड़कों का सुधार हुआ है। ऊर्जा क्षेत्र में 1.72 बिलियन यूएस डॉलर, 140 शहरों के विकास में 800 मिलियन डॉलर का सहयोग मिला। इससे जल आपूर्ति, सीवरेज, स्वच्छता, वर्षा जल निकासी और टोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार में मदद मिली है। इसके अलावा 1 लाख 25 हजार हेक्टेयर में सिंचाई के लिये 375 मिलियन यूएस डॉलर का सहयोग मिला है।

पिछले पांच सालों में मध्य प्रदेश के कर्ज में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। मार्च

2020 में राज्य पर 2.01 लाख करोड़ रुपये का कर्ज था। मार्च 2024 तक यह आंकड़ा बढ़कर 3.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। अनुमान है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक यह 4.21 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार को हर साल 750,000 करोड़ सिर्फ कर्ज के ब्याज चुकाने में खर्च करने पड़ रहे हैं। अगर ब्याज की राशि बचाया जाता तो इसका इस्तेमाल सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य विकास कार्यों में हो सकता था। इसी मुद्दे पर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटार ने कहा है कि राज्य में वित्तीय इमरजेंसी जैसे हालात हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी आंकड़ों और केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक

देश में सबसे ज्यादा कर्ज तमिलनाडु पर है, जो वित्त वर्ष 2024-25 की समाप्ति तक 8 लाख 34 हजार 543 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश (7,69,245.3 करोड़), तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र (7,22,887.3 करोड़), चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल (6,58,426.2 करोड़), पांचवें नंबर पर कर्नाटक (5,97,618.4 करोड़), छठे नंबर पर राजस्थान (5,62,494.9 करोड़), सातवें नंबर पर आंध्र प्रदेश (4,85,490.8 करोड़), आठवें नंबर पर गुजरात (4,67,464.4 करोड़), नौवें नंबर पर केरल (4,29,270.6 करोड़), दसवें नंबर पर (मध्य प्रदेश 4,18,056 करोड़), ग्यारहवें नंबर पर तेलंगाना (3,89,672.5 करोड़) और 12वें नंबर

पर बिहार (3,19,618.3 करोड़) शामिल है।

सरकार का कहना है कि ये कर्ज पूरी तरह पूंजीगत व्यय, यानी अधोसंरचनात्मक विकास कार्यों पर खर्च किया जा रहा है। वित्तीय अधिकारियों के अनुसार, प्रदेश की वित्तीय स्थिति स्थिर है और राज्य ने कभी भी राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से लिया गया सारा कर्ज विकास कार्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है, जो राज्य के दीर्घकालिक विकास के लिए आवश्यक है। जनता के मन में सवाल है कि क्या राज्य सरकार अपने वित्तीय खर्चों में कटौती करेगी या कर्ज का बोझ और बढ़ता रहेगा?

- राज कुमार सिन्हा
बरागी बांध विस्थापित एवं प्रभावित संघ, जबलपुर

